



## पाकिस्तान की राजनीति और जुल्फिकार अली भुट्टो

डा. विनय बहादुर पाण्डेय  
पाठ्यालय इतिहास विभाग  
लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

जुल्फिकार अली भुट्टो 1953 में पारिवारिक समस्याओं के कारण पाकिस्तान वापस लौटकर आये। कुछ समय पश्चात कराँची में उन्होंने वकालत शुरू करने के लिए एक दफ्तर खोल दिये। भुट्टो फौजदारी और दीवानी दोनों ही तरह के मुकदमों की पैरवी करने वाले विख्यात वकील श्री रामचन्द्रानी के साथ प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन रामचन्द्रानी कुछ समय पश्चात ही भुट्टो को अपना प्रतिद्वन्दी समझने लगे और वे भुट्टो को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित करने लगे। भुट्टो के मन में राजनीति के प्रति लगाव पहले से तो था ही परन्तु वे यह सोचते थे कि वकालत और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो ने भी जुल्फिकार को समझाये थे कि राजनीति में समय से पहले घुसना अपने आपको खतरों में डालना है और वहाँ से फिर बाहर निकल पाना सम्भव नहीं होता है, भुट्टो के वकालत शुरू करने वकालत के कुछ समय पश्चात उनकी ही गणना वहाँ के प्रतिष्ठित बड़े वकीलों में होने लगी। भुट्टो अपने पास आये सभी मुकदमों प्रायः हत्या सम्बन्धी मुकदमों उन्होंने बिना किसी अपवाद के ही उन मुकदमों पर जीत हासिल की लेकिन भुट्टो का मन वकालत में नहीं लगता था वे राजनीति में आना चाहते थे। ताकि वह पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए भुट्टो ने पाकिस्तान की राजनीति में हिस्सा लेना आरम्भ कर दिया उस समय पाकिस्तानी सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के विभिन्न प्रान्तों को समाप्त करने का एक निर्णय लिया था जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान की जनता ने सरकार के विरुद्ध प्रबल विरोध करने का निर्णय लिया था और भुट्टो के लिए यह एक अच्छा मौका था और वे इस विरोध पर चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध किया। इसी दौरान भुट्टो को सिंघ यूथ फ्रन्ट का अध्यक्ष चुन लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रान्तों को समाप्त कर एक प्रान्त बनाये जाने की भुट्टो ने तीव्र आलोचना की और उन्होंने उस समय एक पम्फलेट भी लिखा—जिसका शीर्षक था “पाकिस्तान संघ राज्य है।” समय सिन्ध की सरकार का नेतृत्व श्री खोरी कर रहे थे। श्री खोरी ने भुट्टो को कई बार गिरफ्तार करने के बारे में गम्भीरता से सोचा। परन्तु उस समय भुट्टो परिवार का इतना प्रभाव था कि उनका सोचना असफल रहा। क्योंकि भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो को सिंघ का निर्माता माना जाता था। ऐसी स्थिति में श्री खोरी ने भुट्टो के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाये। लेकिन भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो ने एक बार पुनः भुट्टो को समझाये कि राजनीति में समझदारी से काम करना चाहिए इसलिए भुट्टो कुछ दिनों के लिए चुप बैठ गये। भुट्टो का परिवार भी एक राजनीतिज्ञ था इसलिए पारिवारिक सम्बन्धों के कारण भुट्टो समय से पहले ही सरलता से राजनीति में प्रवेश पा लिए। क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा भुट्टो के परिवार पिता शाहनवाज भुट्टो के घनिष्ठ मित्रों में से थे। उस समय सर्दियों में जब भी कभी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा और जरनल अयूब खान लरकाना आते थे, तो भुट्टो के पिता सर शाहनवाज भुट्टो उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित करते थे। और उनके इस निमन्त्रण का वे लोग बड़ा सम्मान करते थे तथा भुट्टो के घर आते थे। इन अवसरों पर जुल्फिकार अली भुट्टो भी घर उपस्थित रहते थे। 1955 में पहली बार जुल्फिकार अली भुट्टो की बातचीत पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से हुई। इस्कंदर मिर्जा भुट्टो की बातों से बहुत प्रभावित हुए। 1957 ई. में जुल्फिकार अली भुट्टो को कराँची का मेयर बनाये जाने पर भी विचार हो रहा था लेकिन भुट्टो ने इसे अस्वीकार कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कह दिया कि वे ऐसे पदों पर काम करना नहीं चाहते जिसका चुनाव होता हो, यह उनके अन्दर अलोक तान्त्रिक रूख का एक प्रमाण कह सकते हैं। भुट्टो चुप नहीं बैठने वाले थे वे सिन्ध के अन्दरूनी इलाकों में राजनीति काम करते रहे।

सिम्बर 1957 ई0 में भुट्टो को अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल का सदस्य चुन लिया गया। इस चुनाव से भुट्टो का राजनीतिक कैरियर में प्रवेश हो गया। भुट्टो को काफी प्रसन्नता हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की छठी कमेटी में आक्रमण की परिभाषा का जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाषण दिया। जो आज भी कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। भुट्टो अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते ही विदेशों में अपना प्रभाव जमाने की कोशिशें शुरू कर

दी। उस समय भुट्टो की आयु मात्र 29 वर्ष थी। 1958 ई० में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुहरावर्दी को प्रधानमंत्री पद से हटा कर नये प्रधानमंत्री फिरोजखान नून को बनाया गया। सन् 1958 ई० में प्रधानमंत्री फिरोजखान नून जुल्फिकार अली भुट्टो को जेनेवा में समुद्री कानून के बारे में अमेरिकी सम्मेलन में जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने का कार्यभार सौंप दिया। भुट्टो ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। अब भुट्टो की प्र'त्सा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। इस सम्मेलन में इनकी प्रस्तुति काफी सराहनीय और प्र'त्सनीय रही। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी राजनैतिक स्थिति विदे'गे दे'गे में प्रतिष्ठा प्राप्त करके बनाई थी। पाकिस्तान के बहुत बड़े जनमत को लेकर वह पाकिस्तान की राजनीति में नहीं आये थे।

उस समय पाकिस्तान की राजनीति में काफी उथल पथल चल रहा था। 7 अक्टूबर 1953 ई० में रात्रि लगभग साढे बजे इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को रद्द करते हुए केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों को बरखास्त करते हुए तथा संसदीय व प्रान्तीय विधान सभाओं को भंग करते हुए, सभी राजनीतिक दलों को खत्म करते हुए और अयूब खान के नेतृत्व में पूरे पाकिस्तान में मा'ल लॉ स्थापित करने की घोषणा जारी की। इस्कंदर मिर्जा ने 27 अक्टूबर 1958 ई० को नई सरकार की घोषणा की। इस सरकार में अयूब खॉ को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी दिन को शाम को अयूब और अन्य जनरल मिर्जा से मिले और अत्यन्त सम्मान के साथ उनसे पे'गे आय। 27-28 अक्टूबर की रात पाकिस्तान के लिए बड़ी नाटकीय थी। रात को लगभग दस बजे एक नौकर ने राष्ट्रपति के शयन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि कुछ जनरल उनका इंतजार कर रहे हैं। उन जनरलों ने मिर्जा को राष्ट्रपति पद से हटने के लिए अयूब खॉ के संदे'गे को दिया। इस प्रकार से पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि अयूब खॉ ने दिन में प्रधानमंत्री की शपथ ली और रात में वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गये।

इसी दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो को भी अयूब खॉ ने अपनी नई सरकार में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। बाकी परिस्थितियों को देखते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो भी पहले तख्ता पलट को काफी शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन मिलिटरी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान में मा'ल लॉ को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और मिलिटरी सरकार हालात को पहले की तरह लाने की पूरी को'त्ति करेगी। शायद वो प्रजातन्त्र के सच्चे दौर को लाने के लिए एक नया रास्ता बनाए। अतः मित्रता और असैनिक प्रतिभा के विचार को रखने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को अयूब के मंत्रीमण्डल में वाणिज्य मंत्री के रूप में चुना गया। जब कि इससे पहले भुट्टो ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून सम्बन्धी कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल को प्रतिनिधित्व कर चुके जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री पर रहते हुए पाकिस्तान के निर्यात व्यवस्था पर नियन्त्रण स्थापित किया और भुट्टो ने निर्यात केन्द्रों का निर्माण किया। वाणिज्यमंत्री भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया कि जून 1959 के अन्त तक विदे'गी व्यापार संगठनों के सुधारों को पूरा कर दिया जायेगा। भुट्टो ने वाणिज्य मंत्री पद पर रहते बहुत ही उल्लेखनीय कार्यों को किया जिसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य पाकिस्तान में बोनस बाउचर स्कीम को लागू करना था। भुट्टो ने यह स्कीम पाकिस्तान के निर्यात व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लागू किये थे।

भुट्टो द्वारा इस स्कीम को लागू करने का उद्दे'य था कि पाकिस्तान के निर्यात व्यवस्था में मदद मिल सके। यह स्कीम जर्मनी के एक अर्थ'शास्त्री के द्वारा बनाई गयी थी। इस स्कीम को लागू करने के उपरान्त पाकिस्तान के व्यापार सन्तुलन पर तुरन्त असर पड़ा। जिससे पाकिस्तान के निर्यात व्यवस्था में बढ़ोत्तरी हुई। इस स्कीम को भुट्टो ने पाकिस्तान की तत्कालीन अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लागू किया था लेकिन पाकिस्तान ने इस अपनी बैसाखी बना ली जिसके कारण आगे चलकर इस व्यवस्था में कमियाँ आने लगी इस लिए जब भुट्टो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस स्कीम को समाप्त कर दिया। भुट्टो जानते थे कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो इन्हें पाकिस्तान की जनता के बारे में अव'य सोचना पड़ेगा और जनता के लिए काम भी करना पड़ेगा। भुट्टो के इस प्रकार के कार्यों को देखकर पाकिस्तान की सरकार ने इनकी सराहना की। भुट्टो की कार्य करने की क्षमता से पाकिस्तानी जनता भी काफी खु'गी थी।

राष्ट्रपति अयूब खॉ की सरकार पाकिस्तान की जनता में काफी लोकप्रिय हो गयी थी। अयूब खॉन राष्ट्रपति बनने के प'चात उन्होंने शुरुआती महीनों में पाकिस्तान में कई सुधार किये। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाये और भ्रष्टाचार विरोधी एक कानून भी बनाया। जिससे जनता में उनकी बहुत प्र'त्सा होने लगी। जुल्फिकार अली भुट्टो भी अयूब खॉन की काफी प्र'त्सा करने लगे थे। भुट्टो एक ऐसे समय के इन्तजार में थे कि वह कब राष्ट्रपति अयूब खॉन के प्रति अपनी वफादारी को साबित करें। इसी दौरान भुट्टो जकोवाबाद की

यात्रा पर गये। इस यात्रा के दौरान भुट्टो ने जकोवाबाद में एक भाषण-दिया। अपने इस भाषण में भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खॉन की खूब प्रशंसा की और कहा कि वह एक निडर नेता है।

जुल्फिकार अली भुट्टो अपने कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए पहली बार अक्टूबर 1959 ई. में संयुक्त राष्ट्रसंघ में हो रहे प्रतिनिधि मण्डल सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति अयूब खॉन ने ही इस प्रतिनिधि मण्डल के नेतृत्व के लिए भुट्टो को चुना था। जुल्फिकार अली भुट्टो को 31 वर्ष की अवस्था में ही ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो गया। भुट्टो के लिए यह बहुत ही फर्क की बात थी। भुट्टो ने अपने इस कार्य को अत्यधिक सफलता पूर्वक निभाया। राष्ट्रपति अयूब खॉन के शासन के दौरान भुट्टो का यह पहला अवसर था कि उन्होंने अन्तराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अपने इस दायित्व को सहर्ष निभाया। इस सम्मेलन में भुट्टो ने पाकिस्तान का नेतृत्व करते हुए निःस्त्रीकरण का धारा प्रवाह व्याख्या की और उन्होंने सोवियत संघ व ब्रिटिश के निःस्त्रीकरण प्रस्ताव का भी संक्षिप्त वर्णन किया। भुट्टो अन्तराष्ट्रीय कानून के विद्यार्थी रह चुके थे, इसलिए वे इस प्रकार धारा प्रवाह बोलने में सक्षम थे। भुट्टो ने इस सम्मेलन के पहले भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में अन्तराष्ट्रीय मंच पर बोल चुके थे। जनवरी 1960 ई. में पाकिस्तानी सरकार ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सूचना एवं राष्ट्रीय पुर्न निर्माण से सम्बन्धित विभागों के मंत्रालयों का कार्य भार सौंप दिया। राष्ट्रपति अयूब खॉन द्वारा यह मंत्रालय भुट्टो को सौंपने का कारण यह था कि वे अपने दायित्व का निर्वाह बड़े ही सहज ढंग से कर रहे थे। जिसके कारण पाकिस्तान में अयूब खॉन के सरकार की काफी प्रशंसा हो रही थी। भुट्टो भी अयूब खॉन की काफी प्रशंसा करते थे। अयूब खान भुट्टो से काफी प्रभावित थे। अयूब खॉन द्वारा भुट्टो को सूचना मंत्रालय देने का उद्देश्य यह था कि उनके शासन के दौरान होने वाली घटनाओं को उन्हें बताना था और उस पर विचार-विमर्श करके उस पर एक सही निर्णय लेना था।

अक्टूबर 1960 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ के 15वें अधिवेशन में जुल्फिकार अली भुट्टो की अध्यक्षता में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने भाग लिया। यह अधिवेशन भुट्टो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में कई अन्तराष्ट्रीय महान हिस्तियाँ खुशेव मैकमिलन और फिडलकैस्ट्रो भी शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में भुट्टो इन महान हस्तियों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खड़े हुए थे। इस प्रकार से भुट्टो की चर्चा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी थी। भुट्टो ने जब ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के पद को संभाले थे। तब उस समय सोवियत संघ ने पाकिस्तान के समक्ष तेल अनुसंधान में पाकिस्तान की मदद करने का प्रस्ताव रखा था। सोवियत संघ के इस प्रस्ताव पर उस पाकिस्तान सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी इसलिए भुट्टो को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के विदेशी सम्बन्धों में ऐतिहासिक परिवर्तन किये। भुट्टो पाकिस्तान का पीछमी देगों पर निर्भरता से सन्तुष्ट नहीं थे। वे पाकिस्तान की निर्भरता को सन्तुलित करने के लिए व्याकुल थे। इसी कारण भुट्टो कम्यूनिष्ठ और साम्यवादी गुट से सम्बन्ध स्थापित करने की नीति पर बल दे रहे थे। भुट्टो ने जब प्राकृतिक अनुसंधान मंत्रालय को सम्भाला तब उन्होंने राष्ट्रपति अयूब खॉन को सोवियत संघ के तेल सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया और भुट्टो ने सोवियत संघ के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। अक्टूबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन से वापस पाकिस्तान लौटने के बाद भुट्टो ने कहा कि मैं जल्द ही निकट भविष्य में क्रेडिट एग्रीमेन्ट और तेल अनुसंधान के विषयों पर सोवियत संघ से तकनीकी मदद प्राप्त करने के सिलसिले से मास्को जाऊँगा। अन्ततः पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के साथ भुट्टो मास्को पहुँच गये। सोवियत संघ ने भुट्टो के स्वागत सत्कार के लिए क्रेमलिन में एक समारोह का आयोजन किया था। इस स्वागत समारोह में भुट्टो गये और वहाँ पर इनकी मुलाकात खुशेव से हुई। खुशेव ने भुट्टो का स्वागत किया। खुशेव से भुट्टो की यह दूसरी मुलाकात थी पहली मुलाकात अभी कुछ ही महीनों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 15वें अधिवेशन के जनरल असेम्बली में भुट्टो ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में खुशेव ने मैकमिलन के भाषण के दौरान अपना जूता उतार कर टेबल पर पीटना शुरू कर दिया था। खुशेव द्वारा इस प्रकार के अभद्र व्यवहार करने के कारण वह विभव भर में सुर्खियों में आ गये थे। इस मुलाकात के दौरान भुट्टो और खुशेव के बीच काफी नजदीकी सम्बन्ध स्थापित हो गये। खुशेव और भुट्टो के बीच काफी बातचीत हुई। भुट्टो लिखते हैं कि “मैं खुशेव को बेहद पसन्द करता हूँ और वह भी मुझसे स्नेह रखते हैं, सोवियत यात्रा के दौरान हम दोनों लोगों के बीच काफी दिलचस्प बातें हुई थी।”

जुल्फिकार अली भुट्टो मास्को की यात्रा के दौरान सोवियत संघ से जो संधि प्रारूप का खाका लाये थे वह भुट्टो की एक बड़ी जीत थी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की विदेशी नीति जो कई वर्षों से एक ही जैसी चली आ रही थी, भुट्टो के कारण उसमें व्यापक परिवर्तन आया। पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच संधि पर बड़ी

उलझनों के बाद हस्ताक्षर हुए। “इस संधि में भुट्टो सोवियत संघ के सामने 30 मिलियन डालर ऋण के रूप में माँगा था। पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच वार्तालाप के शुरूआती दौर में सोवियत संघ इस बात पर अड़ा था कि वह इस ऋण को पाँच प्रतिशत व्याज दर पर ही देगा। भुट्टो इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने सोवियत संघ को पूर्व के सन्दर्भों का उल्लेख करके यह याद दिलाया कि सोवियत संघ ने पहले ढाई प्रतिशत व्याज दर पर यह ऋण देने के लिए राजी था। लेकिन सोवियत संघ भुट्टो की बातों से सहमत नहीं हुआ। इस प्रकार से यह संधि असफल होती नजर आने लगी। भुट्टो यह जानते थे कि पाकिस्तान की कैबिनेट पाँच प्रतिशत व्याज पर ऋण की मंजूरी कभी नहीं देगी। इस कारण भुट्टो बड़ी ही झुझलाहट से इस संधि के लिए मना कर दिए और उन्होंने अपने अगले दिन की लेनिन गार्ड की प्रस्तावित यात्रा को रद्द रक दिया, तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्यों को अपना सामान बाँधने को कहा। भुट्टो के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सोवियत संघ के लोग काफी व्याकुल हो रहे थे अन्ततः सोवियत संघ ने अपना फैसला वापस लेते हुए ढाई प्रतिशत व्याज पर धन देने के लिए राजी हो गया। भुट्टो की इस प्रकार की चतुराई के कारण पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल न मात्र ढाई प्रतिशत के मामूली व्याज दर पर 30 मिलियन डॉलर ऋण के रूप में लेकर पाकिस्तान वापस लौट आया। सोवियत संघ के मंत्री श्री मिकोयॉन जो इस मामले को देख रहे थे वह भुट्टो के इस प्रकार के सौदेबाजी के कौशल से बहुत प्रभावित हुए और पाकिस्तानी राजदूत आगा हिलाले से मास्को में कहे कि “भुट्टो कम उम्र का एक जवान और चालाक व्यक्ति है”। भुट्टो ने जो 30 मिलियन डालर ऋण तेल समझौते के लिए पाकिस्तान लेकर आये तो उसको लेकर कैबिनेट में जो विरोध हो रहा था उस पर उन्होंने पुनः विचार किया और कहा कि इस समझौते में जो अड़चने हैं वह मेरी सरकार के हैं। भुट्टो लिखते हैं कि अयूब खॉन की कैबिनेट के ही कुछ प्रभावशाली मंत्री ही उनको सलाह देते हैं कि तेल समझौते के लिए की गई यात्रा अविचारणीय है। लेकिन भुट्टो इन कड़े विरोध के बावजूद भी इस समझौते को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञा थे अन्ततः इस समझौते पर पाकिस्तानी सरकार ने हस्ताक्षर कर ही दिया। यह पाकिस्तान के लिए साम्यवादी गुट के साथ सम्बन्ध बनाने का पहला प्रस्ताव था जो कि पश्चिमी नीति के खिलाफ था। इस समझौते में पाकिस्तानी जनता भी भुट्टो के साथ थी। इस समझौते का पाकिस्तानी जनता ने काफी उत्साह के साथ स्वागत किया। भुट्टो को पाकिस्तान में चारों ओर इस निर्णायक फैसले के निर्माता के रूप में स्वीकार किया। इतने विरोध के बावजूद भी भुट्टो अपने मकसद में कामयाब रहे और उनकी इस कामयाबी ने उन्हें एक दृढ़निश्चय एवं एक निर्विरोधी स्वतन्त्र राजनेता के रूप में स्थापित किया व आगे उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक नये मार्ग को प्रोत्साहित किया।

जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। मार्च 1960 ई0 में अयूब खॉन ने भुट्टो को कश्मीर समस्या का भी भार सौंपा था। अयूब खॉ इस समय कोई भी विदेशी मामला होता था तो वह भुट्टो से ही सलाह लेकर करते थे एक प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय भुट्टो राष्ट्रपति अयूब खॉ के सबसे करीबियों में से थे। भुट्टो की बातों को अयूब खॉन काफी एहमियत देते थे। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या के अलावा नदी-जल विवाद भी एक समस्या थी इस समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर काफी प्रयास किये गये लेकिन यह समस्या इतनी जटिल थी और दोनों पक्षों का रवैया इतना कठोर था कि कोई स्थायी समाधान निकाला नहीं जा सका। आखिरकार विन् व बैंक की मध्यस्थता व सक्रिय प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप एक लम्बे प्रयास के उपरान्त दोनों देशों के मध्य नदी-जल विवाद के समाधान हेतु एक स्थायी समझौता करने में सफलता प्राप्त हुई। यह समझौता भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों की सुदृढ़ता में एक महान कदम माना जा रहा था। परिणामतः इस समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू ने 19 सितम्बर 1960 ई0 को पाकिस्तान की पाँच दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खॉन ने नदी-जल समझौते पर हस्ताक्षर कर एक नये अध्याय की शुरुआत की। यह समझौता खासकर पाकिस्तान के लिए फायदे मन्द साबित हुआ। क्योंकि इस संधि की शर्तों के आधार पर भारत सिर्फ पाकिस्तान को सारी की सारी पश्चिमी नदियों को आवंटित करने के लिए सहमत नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी भी तीनों पूर्वी नदियों-रावी, व्यास और सतलुज से भी उस समय तक पाकिस्तान को पानी देने के लिए सहमत हुआ, जब तक कि पाकिस्तान अपनी-सिंचाई व्यवस्था करने में समर्थ न हो जाय। इस सन्धि से सिन्धु जल परियोजना के विकास के लिए एक कोष स्थापित किया गया। इस कोष में अमेरिका ने 725 मिलियन डालर व भारत ने 175 मिलियन डालर का योगदान देने का निश्चय किया। इस कोष का उद्देश्य पाकिस्तान में सिंचाई परियोजना की विकास योजनाओं को एक साकार रूप देना था। जुल्फिकार अली भुट्टो इस सन्धि पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद राष्ट्रपति अयूब खान से जाकर मिले और उनसे कहे कि वह कश्मीर झगड़े को छोड़कर और सारे मसलों को भूल जायें और प्रधानमंत्री पं0 नेहरू को यह बता दे कि पाकिस्तान को भारत के साथ एक ऐसा समझौता करने की बेहद फिक्र है जो कश्मीर की जनता की जायज इच्छाओं को पूरा कर दे। पं0 नेहरू पाकिस्तान में पाँच दिन तक रहे। राष्ट्रपति अयूब खॉ के साथ उनकी कई बार बातचीत हुई कश्मीर की समस्या पर दोनों



तरफ के विचारों को जानने के बाद इस वार्तालाप के समाप्त होने पर एक विज्ञप्ति जारी की गई। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अयूब ने बड़ी ही नम्रता से बातचीत किये और उन्हें सलाह दिये कि वह खुल कर साँस ले और किसी बात की चिन्ता न करे। लेकिन भुट्टो मायूस थे सच तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में मायूसी छा गयी थी कि क'भीर के झगड़े को समाप्त करने के सिलसिले में बात आगे नहीं बढ़ पायी।

भारत के प्रधानमंत्री पं० नेहरू के अपने दे'गे लौट जाने के दो दिन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति अयूब खॉन से मुलाकात किये और उन्हें बताया कि उस विज्ञप्ति की तरफ आम जनता का रवैया काफी उपेक्षा जनक है और जनता क'भीर समस्या के बारे में क्या सोच रही है, भुट्टो इस बात को अयूब के दिल में पूरी तरह से बिठा दिये कि भारत के इरादे नेक नहीं है। इस लिए नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर के समय दोनों दे'गो के मध्य मैत्री सम्बन्ध अपने चरमोत्कर्ष पर थे लेकिन इस समझौते के तुरन्त बाद दोनों दे'गो के मधुरता पूर्ण सम्बन्ध धीरे-धीरे कटुता की ओर बढ़ने शुरू हो गये। राष्ट्रपति अयूब खॉन ने अक्टूबर 1960 ई० के शुरू में आजाद क'भीर के कुछ हिस्सों का दौरा किये। उनके इस दौरे का खास मकसद था। राष्ट्रपति अयूब खॉन ने 6 अक्टूबर 1960 ई० को क'भीर (मुजफ्फराबाद) में भाषण देते हुए कहा कि "पाकिस्तान भारत के साथ तब तक सहयोग की भावना नहीं रख सकता जब तक कि क'भीर समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पाकिस्तानी सेना क'भीर को अनिश्चित काल तक अनसुलझा नहीं रख सकती। भारत में राष्ट्रपति अयूब खॉन के उक्त वक्तव्य पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई और इस घोषण को नदी-जल समझौते के दौरान उत्पन्न मैत्री पूर्ण भावना पर कड़ा प्रहार बताया गया। भारत के प्रमुख पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया ने अपने सम्पादकीय में इसे राष्ट्रपति अयूब की धमकी की संज्ञा दी गयी। इस घटना के तुरन्त प'चात पण्डित नेहरू ने न्यूयार्क में अपनी वार्ता के दौरान क'भीर समस्या को एक पिटारे की संज्ञा दी और कहे कि इसे न खोलने में ही अकलमन्दी है। भुट्टो ने लिखा है कि "मुझे इस से बहुत खु'गी हुई कि राष्ट्रपति अयूब खॉ भारत के प्रधानमंत्री पं० नेहरू की न्यूयार्क में कही हुई बात से काफी नाराज हुए और राष्ट्रपति अयूब खॉन ने इस बात जवाब देने के लिए मेरी कही हुई बातों को इस्तेमाल किये और राष्ट्रपति अयूब खॉन ने कहा कि क'भीर समस्या पिटारा नहीं है, बल्कि एक टाइम बम है, जिसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निष्क्रिय कर दिया जाये"। इस प्रकार से भुट्टो की सलाह पर ही अयूब खॉन विदे'गी निर्णय और बातचीत करते थे। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच क'भीर समस्या को लेकर गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गया था। क'भीर समस्या का कार्यभार पाकिस्तानी सरकार ने भुट्टो को सौपा था। इसलिए यह कार्य भुट्टो के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। जब यह बात एक हकीकत के तौर पर सामने आ गयी कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते की सीधी बातचीत नाकाम हो गयी है तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खॉ से सीधी वार्ता की और भुट्टो ने कहा कि भारत की तरफ से कितना खतरा पैदा हो गया है। इसलिए पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद् से मदद माँगनी चाहिए। भुट्टो की बात को गम्भीरता से लेते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर क'भीर की समस्या को सुरक्षा परिषद् के सामने ले जाने का फैसला लिया। लेकिन सुरक्षा परिषद् में इस समय पाकिस्तान को प'चमी दे'गो का वह समर्थन नहीं मिला पाया जो कि 1955-56 ई० में प्राप्त हुआ था। दिसम्बर 1961 ई० में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि क'भीर के मामले में पाकिस्तान को मौजूदा हालात को ही मान लेना होगा और बातचीत सिर्फ युद्ध विराम रेखा में थोड़े-बहुत हेर-फेर के बारे में हो सकती है। उन्होंने एक ताना'गाह की तरह बात करने की को'गी की। लेकिन क'भीर की समस्या में एक पक्ष पाकिस्तान का भी था और उस समय क'भीर समस्या को भुट्टो देख रहे थे इसलिए उनसे यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि वह पं० नेहरू के बयानों को चुपचाप मान लेंगे।

जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति अयूब खॉ से मुलाकात करके उनसे यह साफ कह दिये कि युद्ध-विराम रेखा के आधार पर क'भीर की समस्या के किसी हल को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और भुट्टो ने अयूब से यह भी कहा कि अगर क'भीर समस्या के सवाल को सुलह समझौते से तय करना नामुमकिन हो तो राष्ट्रपति अयूब खॉ को दूसरे तरीके को भी अपनाने की बात कही। भुट्टो के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की बात कहने की वजह भी थी, क्योंकि भारतीय नेता चाहते थे कि हम उनका हुक्म मानना सीख ले। भुट्टो के सलाह पर सर मुहम्मद जफरुल्ला खॉ ने जनवरी 1962 ई० में सुरक्षा परिषद् की बैठक होने से पहले भुट्टो ने एक बयान तैयार करने में जफरुल्ला खॉ की मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने भी सुरक्षा परिषद् की बैठक आमंत्रित करने के स्थान पर यह सुझाव दिया कि दोनों पक्ष सीधी वार्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूँढें। केनेडी ने यह भी सुझाव दिया कि वि'व बैंक के अध्यक्ष (यूजीन ब्लेक) दोनों पक्षों के मध्य अपनी सद्सेवा प्रदान करे व इस समस्या के समाधान में भी अपने प्रयास करें। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया लेकिन भारत ने इसे तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मानते हुए अस्वीकार कर दिया। भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाये जाने की मांग को बनाये रखा। अतः बिट्रेन ने इस बैठक को आमंत्रित कराने में

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। 1 फरवरी 1962 को कश्मीर समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कश्मीर समस्या के प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन रूस ने भारत के हित को देखते हुए बीटो का प्रयोग करके इस सुरक्षा परिषद की बैठक को असफल बना दिया। कश्मीर समस्या पर भारत को रूस द्वारा मदद करते देख भुट्टो का झुकाव चीन की तरफ हो गया और पाकिस्तान तथा चीन के बीच संबंधों का विकास प्रारम्भ हो गया और भुट्टो ने धीरे-धीरे सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध को कम करने लगे। चीन की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को इस बात का यकीन दिलाने लगी कि दोनों देशों के बीच के हितों की किसी भी टकराव की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसकी वजह से उनके दोस्ती के सम्बन्ध में खतरा उत्पन्न हो सके। जनवरी 1962 ई0 में पाकिस्तान ने सीमा निर्धारण कर लेने के सवाल पर चीन के रवैये को जानने की कोशिश की। भुट्टो ने अयूब खॉं से सलाह करके 28 मार्च 1961 को एक कुटनीतिक नोट चीन को भेजा जिसमें चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने का उल्लेख किया गया था। चीनी सरकार ने इसका जवाब देने में बहुत समय लगा दिया, क्योंकि चीन अपनी फौज भारतीय सीमा के पास जमा करने तथा हुजा और गिलगित के आस-पास चीनी घुसपैठियों के दलों को संगठित करने में व्यस्त था। चीन ने पाकिस्तान के सुझाव को जवाब फरवरी 1962 ई0 में दिया। 3 मई 1962 ई0 को दोनों देशों की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें दोनों देश अपनी सीमा का पता लगाने और उन्हें निर्धारित करने के मसौदे पर बातचीत करने के लिए राजी हो गये। पाकिस्तान-चीन समझौते की वार्ता की घोषणा पर भारत सरकार ने 4 मई 1962 ई0 को एक कड़ा विरोध पत्र पाकिस्तान एवं चीन सरकार को भेजा जिसमें इस घोषणा पर अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों को यह चेतावनी दी कि कश्मीर क्षेत्र (जो कि भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका था) के सम्बन्ध में पाकिस्तान व चीन के बीच होने वाले समझौते को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। चीन ने 31 मई 1962 ई0 को एक पत्र में भारतीय आपत्तियों को टुकराते हुए इसे पाकिस्तान एवं चीन का निजी मामला बताया।

जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी भारत के इस विरोध को टुकरा दिया और कहे कि भारत को कोई अधिकार नहीं है कि वह पाकिस्तान का चीन के साथ बातचीत करने का विरोध करें तथा पाकिस्तान इलाके के उस हिस्से की जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी अभी तक पाकिस्तान कर रहा है। उस सीमा के बारे में चीन के साथ समझौता कर लेने पर भारत कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भुट्टो को अब तक एक अच्छे राजनीतिक नेता के रूप में पाकिस्तान में देखा जा रहा था। भुट्टो भी यह जानते थे कि इन्हें कब और कहाँ क्या बोलना चाहिए। भुट्टो पाकिस्तान के राजनैतिक वातावरण में बने रहने के लिए वे समझते थे कि पाकिस्तानी जनता में क्या भावनाएँ उभर रही हैं। जब भुट्टो को महसूस हुआ कि भारत के विरोध में बोलने पर जनता प्रसन्न रह सकती है तब वे भारत के विरोध में बोलने से भी नहीं चुकते थे।

जुल्फिकार अली भुट्टो अपने राजनैतिक जीवन के विषय में भी सोचते थे और अपने व्यक्तित्व को विश्लेषित भी करते थे। 10 जुलाई 1962 ई0 में राष्ट्रीय असेम्बली में भाषण देते हुए कहे कि—“मैं भी उसी समाज का अंग हूँ। आज मंत्री बनकर यहाँ बोल रहा हूँ, इसका भी यही कारण है कि मैं इस विधायिकाधिकार वर्ग का व्यक्ति हूँ। इसलिए इस व्यवस्था के लाभों को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस व्यवस्था से प्राप्त होने वाले फायदे के बावजूद इस तथ्य के बावजूद कि हममें से अनेक इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए संघर्ष करेंगे—जूझेंगे। इस व्यवस्था में अनेक मौलिक दोष हैं गलतियाँ हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोग टुच्ची बातों के लिए दुरभि संघियों करते हैं। इससे जनता को नुकसान पहुँचता है। अन्य लोगों की निर्धनता के प्रति यह लोग आखें बन्द कर लेते हैं। इससे आलसीपन को प्रोत्साहन मिलता है। ये सामन्तवादी एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं तो गरीब जनता की हालत ज्यों की त्यों बनी रहती है। कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता। कोई कारखाना नहीं लग पाता। कहीं सड़के नहीं बनती, कोई संचार व्यवस्था नहीं हो पाती, बिल्कुल अंधेरा होता है, गरीबों और दुखदायी निर्धनता चारों ओर फैली होती है। केवल कुछ बड़े लोग ही खुशहाल बन पाते हैं। ये अभिमानी जमींदार किन समस्याओं की सुलझाने के लिए आगे आते थे। क्या वे दलित लोगों की भलाई के लिए कुछ सोच पाते थे। भुट्टो के इस प्रकार के विचार से यह प्रकट होता है कि भुट्टो अब एक सामन्तवादी विचार धारा को छोड़कर एक राजनीतिक विचार धारा के अच्छे नेता हो गये हैं। जो कि गरीब जनता के बारे में काफी सोच रहे हैं। पाकिस्तान की गरीब जनता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए विचार कर रहे हैं।

जुल्फिकार अली भुट्टो चीन के साथ पाकिस्तान के सम्बन्ध को सुधारने में लगे थे। परन्तु भारत के साथ कश्मीर समस्या को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। इस समय कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच दीवार बन चुकी थी। इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने के लिए कुछ विदेशी शक्तियाँ सामने आयीं। भारत

और पाकिस्तान के बची समझौता कराने के लिए अमेरिकी राज्य सचिव सैण्डीज व हैरीमान ने नई दिल्ली आकर पण्डित नेहरू और अन्य मंत्रियों से 24 से 27 नवम्बर 1962 ई० के दौरान विचार विमर्श किये। जिसमें कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पुनः नवीन प्रयास करने पर बल दिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खॉन और भारतीय प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हो गये कि दोनों देशों के बीच के विवादों को विनिर्णयक कश्मीर समस्या के समाधान के लिए फिर से प्रयत्न किये जायें। भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति और मित्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्री स्तर पर वार्ता करने व इसके पश्चात दोनों शासनाध्यक्षों के बीच विचार वार्ता करने के लिए अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की।

इस प्रकार दोनों देशों के मुखिया ने कश्मीर समस्या का समाधान करने का विचार कर लिया और दोनों देशों के मंत्रियों के बीच वार्ता 27 दिसम्बर 1962 से 16 मई 1963 तक चली। इस वार्ता में कई समस्याओं पर बल दिया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच खुलकर बातचीत हुई। पाकिस्तान मंत्रियों के प्रतिनिधिकर्ता भुट्टो थे भुट्टो राष्ट्रपति अयूब खॉ के कहने पर इस वार्ता में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे कश्मीर समस्या को भुट्टो काफी सोच विचार कर लेने के उपरान्त ही निपटाना चाहते थे। कश्मीर समस्या पर “चूँकि भारत और पाकिस्तान का मेल-मिलाप कराने के लिए अमेरिकी मंत्री और ब्रिटिश मंत्री आये थे इस लिए पाकिस्तान इन्हे मना तो कर नहीं सकता था और समझौता भी नहीं कर सकता था। क्योंकि 1962 में जब भारत और चीन युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में फिर उथल-पुथल शुरू हुई। पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों ने भारत को दोषी ठहराया। चीन ने भारत पर जब हमला किया तो भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सैनिक सहायता की माँग की। इन दोनों देशों से युद्धयोगी सामान भारत पहुँचने लगा। पाकिस्तान ने इसका बड़ा विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा कि चीन की ओर से भारत पर इस प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर उसको सैनिक सहायता दी जाए, परन्तु पाकिस्तान के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और भारत को सैनिक सहायता मिलती रही। अतः पाकिस्तान के मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इस समस्या को टालत रहे।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्याओं का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कश्मीर समस्या का समाधान इतनी जल्दी सुलझाना काफी कठिन कार्य था। लेकिन भुट्टो इस कार्य को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। अगर हम भुट्टो के अब तक के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि वे किस तरह एक वकील के रूप में पाकिस्तान में अपना भविष्य बना रहे थे और साथ ही साथ पाकिस्तान की राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक भी थे। भुट्टो अपने पिता और बीबी नुसरत भुट्टो के सहयोग से पाकिस्तान की राजनीति में आये। प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अयूब खॉ के मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में भुट्टो विभिन्न पदों पर काम करते रहे। वाणिज्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान की निर्यात व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अल्पसंख्यों के मामले, राष्ट्रीय-पुर्ननिर्माण, नवनिर्मित मंत्रालय, ईंधन, बिजली, प्राकृतिक साधन जैसे मंत्रालयों को उन्होंने सम्भाला। भुट्टो ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा सोवियत संघ से अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए एक तेल सन्धि किये। इस सन्धि से भुट्टो ने सोवियत संघ से 30 मिलियन डालर ऋण के रूप में प्राप्त करने में सफल रहे। इस सन्धि का पाकिस्तान के कैबिनेट के कुछ प्रभावशाली लोगो ने विरोध भी किया, लेकिन पाकिस्तान की जनता के सहयोग से भुट्टो को यह सन्धि करने में सफलता प्राप्त हो गयी। इस प्रकार भुट्टो पाकिस्तान की जनता के भी प्रिय हो गये।

### सन्दर्भसूची

1. “पीलू-मोदी” जुल्फी माई फ्रैण्ड” थामसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड, पब्लिकेशन डिविजन दिल्ली 1973
2. सतनाम सिंह, “बीबी बेनजीर और पाकिस्तान की राजनीति” विभवभारती पब्लिकेशन, दिल्ली-2008
3. हरि प्रकाश त्यागी, “भुट्टो की कानूनी हत्या” अनुराग प्रकाशन महरौली नई दिल्ली-1979
4. राम नरेश सिंह, “पाकिस्तान की हकीकत” विवा प्रकाशन पटना-2003
5. हुमायूँ मिर्जा, “फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान” यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका-1999
6. सलमान तासीर, “भुट्टो पालिटिकल बायोग्राफी” विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली-1980
7. दिलीप मुखर्जी, “जुल्फिकार अली भुट्टो क्वेष्ट फॉर पावर” विकास पब्लिकेशन हाउस दिल्ली-1972
8. अनुपम त्यागी, “भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध” रिजेन्सी प्रकाशन नई दिल्ली-2004
9. भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, एक विरोधाभास, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सितम्बर 1965
10. बुरहानुद्दीन मुमिन, “भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध” प्रिन्टवैल प्रकाशन जयपुर-1995
11. बंगीलाल काक, “जुल्फिकार अली भुट्टो, डायरी के आखिरी पन्ने” राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली- 1979

12. के.के. काल, "एशिया का उद्भव एवं विकास" उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ-1988
13. अनिल कुमार, "भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध" इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली-2005
14. स्टेनले ए. वूल्वर्ट, "जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान: हिज लाइफ एण्ड टाइम्स" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क-1993
15. के.पी.मिश्रा, "दि रोल ऑफ दि यू.एन. इन दि इन्डो-पाकिस्तान कान्टीनेन्ट" विकास पब्लिकेशन दिल्ली-1971
16. गैव बहादुर सिंह, "पाकिस्तान शासन एवं राजनीति" गंगाराम एण्ड ग्रैंडसन्स वाराणसी-2002